

International Journal of Social Science and Education Research



ISSN Print: 2664-9845
ISSN Online: 2664-9853
Impact Factor: RJIF 8.42
IJSSER 2025; 7(2): 563-566
www.socialsciencejournals.net
Received: 25-07-2025
Accepted: 28-08-2025

डॉ. अंशु प्रिया

पीएच. डी., समाजशास्त्र विभाग,
सामाजिक विज्ञान संकाय, भूपेंद्र नारायण
मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार,
भारत

निर्धन वर्ग के लिए विश्व बैंक की कल्याणकारी योजनाओं का अध्ययन

अंशु प्रिया

DOI: <https://doi.org/10.33545/26649845.2025.v7.i2g.404>

सारांश

विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका प्रमुख उद्देश्य निर्धन वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना और वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन करना है। निर्धन वर्ग विकासशील देशों की सबसे संवेदनशील आबादी है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहती है। विश्व बैंक ने इन चुनौतियों से निपटने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएँ प्रारम्भ की हैं। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, मातृ-शिशु पोषण कार्यक्रम, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, तथा सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने जैसी योजनाएँ प्रमुख हैं। इसके साथ ही स्वच्छ जल, स्वच्छता और ग्रामीण आवास जैसे बुनियादी ढाँचे के विकास में भी सहयोग किया जा रहा है। इन योजनाओं से निर्धन वर्ग की जीवन गुणवत्ता में आंशिक सुधार हुआ है और गरीबी दर में कमी आई है। तथापि योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी और वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँच की बाधाएँ अभी भी मौजूद हैं। अतः स्थानीय शासन की पारदर्शिता, जनसहभागिता और तकनीकी नवाचार को मजबूत कर इन योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सकता है। इस प्रकार, विश्व बैंक की पहलें निर्धन वर्ग के समग्र विकास और सतत आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करती हैं।

शोध का उद्देश्य

1. निर्धन वर्ग के लिए विश्व बैंक द्वारा संचालित योजनाओं का विश्लेषण करना।
2. इन योजनाओं के प्रभाव और चुनौतियों का अध्ययन करना।
3. भारत और विशेषकर बिहार के संदर्भ में इन योजनाओं की प्रासंगिकता को समझना।

कुटशब्द: सामाजिक सुरक्षा कवच, स्कूल अवसंरचना, शिक्षक प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण, टीकाकरण

प्रस्तावना

विश्व बैंक (World Bank) एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका प्रमुख उद्देश्य विकासशील और अल्पविकसित देशों में गरीबी उन्मूलन तथा सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना है। निर्धन वर्ग विश्व की सबसे कमजोर और वंचित आबादी का हिस्सा है, जिसके जीवन स्तर को ऊपर उठाना वैश्विक विकास एजेंडे का अहम हिस्सा है। विश्व बैंक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और ऋण सहायता के माध्यम से गरीब वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता है।

विश्व बैंक की कल्याणकारी योजनाएँ

विश्व बैंक निर्धन वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएँ संचालित करता है। इनका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में यह संगठन मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार, कुपोषण उन्मूलन, टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सहयोग प्रदान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा तक पहुँच, स्कूल अवसंरचना, शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा संसाधन उपलब्ध कराने में इसकी योजनाएँ सहायक हैं¹

रोजगार और आजीविका सुरक्षा हेतु विश्व बैंक कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन और लघु उद्योगों के वित्त पोषण में सहयोग देता है। ग्रामीण और शहरी निर्धन वर्ग के लिए स्वच्छ पेयजल, शौचालय निर्माण, सस्ती आवास योजना तथा आधारभूत ढाँचे का विकास भी इन योजनाओं का अहम हिस्सा है। इसके अतिरिक्त नकद अंतरण (Cash Transfer), पेंशन व बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ गरीब परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान करती हैं²

Corresponding Author:

डॉ. अंशु प्रिया

पीएच. डी., समाजशास्त्र विभाग,
सामाजिक विज्ञान संकाय, भूपेंद्र नारायण
मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार,
भारत

इन योजनाओं से निर्धन वर्ग की आय, शिक्षा और स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है, किंतु पारदर्शिता, क्रियान्वयन की कमी और स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। फिर भी विश्व बैंक की पहल निर्धन वर्ग के उत्थान और वैश्विक गरीबी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पोषण और स्वास्थ्य योजनाएँ

विश्व बैंक सदैव गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। निर्धन वर्ग की सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य असमानता और पोषण की कमी है, जिससे न केवल उनकी उत्पादकता प्रभावित होती है, बल्कि आर्थिक विकास की गति भी धीमी हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए विश्व बैंक ने स्वास्थ्य और पोषण संबंधी कई कल्याणकारी योजनाएँ प्रारंभ की हैं।³

पोषण के क्षेत्र में विश्व बैंक विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य कुपोषण उन्मूलन, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, तथा सुरक्षित खाद्य और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। भारत में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (ICDS) और पोषण अभियान जैसे कार्यक्रमों को विश्व बैंक का सहयोग प्राप्त हुआ है। ये कार्यक्रम विशेषकर निर्धन वर्ग के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लक्षित करते हैं ताकि प्रारंभिक आयु में पोषण की कमी से होने वाले शारीरिक और मानसिक विकास अवरोध को रोका जा सके।

स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत विश्व बैंक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के आधुनिकीकरण, टीकाकरण कार्यक्रमों के विस्तार और संक्रामक रोग नियंत्रण में सहयोग करता है। इसके अतिरिक्त, मातृ स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा गैर-संचारी रोगों की रोकथाम पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जननी सुरक्षा योजना जैसे कार्यक्रमों को आंशिक वित्तपोषण और तकनीकी सहयोग विश्व बैंक से प्राप्त हुआ है।⁴

इन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट है- कुपोषण दर में कमी, बाल मृत्यु दर में गिरावट, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में वृद्धि और निर्धन वर्ग की जीवन प्रत्याशा में सुधार। हालांकि चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढाँचे की कमी, जन-जागरूकता का अभाव और योजनाओं का असमान वितरण।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विश्व बैंक की पोषण और स्वास्थ्य योजनाएँ निर्धन वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक सिद्ध हुई हैं। यदि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित हो तो सतत विकास और “स्वस्थ समाज” की दिशा में ठोस परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।⁵

शिक्षा सुधार कार्यक्रम

शिक्षा सुधार कार्यक्रमों के तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर बढ़ाने, विद्यालयों की आधारभूत संरचना सुधारने, तथा अध्यापन की गुणवत्ता को उन्नत करने पर बल दिया गया है।

भारत सहित कई विकासशील देशों में विश्व बैंक ने “सर्व शिक्षा अभियान” तथा “समग्र शिक्षा” जैसी योजनाओं में वित्तीय और तकनीकी सहयोग दिया है। इसके माध्यम से निर्धन बच्चों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री, छात्रवृत्ति, तथा मिड-डे मील जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं। इन पहलों से विद्यालय त्याग दर (dropout rate) में कमी आई है तथा विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा मिला है। साथ ही, विश्व बैंक शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग, कौशल विकास और शिक्षक प्रशिक्षण पर भी जोर देता है, जिससे निर्धन वर्ग

के बच्चे केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि रोजगारपरक ज्ञान भी प्राप्त कर सकें।⁶

इस प्रकार शिक्षा सुधार कार्यक्रम निर्धन वर्ग को गरीबी के चक्र से बाहर लाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। यदि इन योजनाओं को स्थानीय प्रशासनिक दक्षता और सामुदायिक सहभागिता के साथ लागू किया जाए तो यह सामाजिक समानता और विकसित भारत की दिशा में ठोस कदम सिद्ध होंगे।

रोजगार सृजन और कौशल विकास

विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य निर्धन वर्ग को गरीबी से बाहर निकालकर आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए रोजगार सृजन और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। निर्धन परिवारों के पास अक्सर संसाधन और शिक्षा की कमी होती है, जिससे वे आर्थिक मुख्यधारा से अलग रह जाते हैं। इस समस्या को दूर करने हेतु विश्व बैंक विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से गरीबों को रोजगारपरक प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और वित्तीय सहयोग प्रदान करता है।

भारत सहित कई विकासशील देशों में विश्व बैंक ने युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, वित्तीय साक्षरता और सूक्ष्म उद्यम (micro enterprise) को प्रोत्साहित किया है। बिहार जैसे राज्यों में कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र में कौशल उन्नयन हेतु परियोजनाएँ संचालित की गई हैं। इससे गरीब वर्ग के लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।⁷

हालाँकि योजनाओं की सफलता क्रियान्वयन, पारदर्शिता और स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी पर निर्भर करती है। यदि इन पहलुओं को मजबूत किया जाए, तो विश्व बैंक की पहलें न केवल रोजगार सृजन में सहायक होंगी, बल्कि निर्धन वर्ग को आत्मनिर्भर बनाकर सतत विकास और “विकसित भारत 2047” की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी।⁸

आवास एवं बुनियादी ढाँचा

निर्धन वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने में आवास और बुनियादी ढाँचा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व बैंक इस क्षेत्र में विशेष परियोजनाओं और वित्तीय सहायता के माध्यम से गरीबों को सुरक्षित और सुलभ आवास तथा बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास करता है। विश्व बैंक के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किरायेती आवास योजना, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास शामिल है।

विश्व बैंक की पहल, जैसे “Affordable Housing” और “Urban Infrastructure Development” कार्यक्रम, झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल आवास प्रदान करना नहीं बल्कि समुदायों में स्थायी सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना भी है। योजनाओं के अंतर्गत, निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को रोजगार देना और ग्रामीण व शहरी गरीबों की सहभागिता सुनिश्चित करना प्रमुख रणनीति है।⁹

इन परियोजनाओं के सकारात्मक प्रभावों में सुरक्षित आवास, बेहतर स्वच्छता, शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे का सुधार, स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार तथा गरीब परिवारों की जीवन गुणवत्ता में वृद्धि शामिल है। हालांकि, इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ भी हैं। लाभार्थियों तक संसाधनों की पहुँच में देरी, भ्रष्टाचार, स्थानीय प्रशासन की कमजोर निगरानी और सांस्कृतिक बाधाएँ प्रमुख समस्याएँ हैं।

इस प्रकार विश्व बैंक की आवास और बुनियादी ढाँचा योजनाएँ निर्धन वर्ग के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यदि इन

परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जनसहभागिता और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए, तो ये योजनाएँ गरीबों की जीवन गुणवत्ता में स्थायी सुधार ला सकती हैं। आवास और बुनियादी ढांचे में सुधार केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम बनता है।¹⁰

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

सामाजिक सुरक्षा निर्धन और वंचित वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक जोखिमों से सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। विश्व बैंक ने विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनेक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का संचालन किया है। इन कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य निर्धन परिवारों को वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य कवरेज, शिक्षा के अवसर और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है।¹¹

विश्व बैंक के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में नकद हस्तांतरण (Cash Transfer), वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी बीमा, स्वास्थ्य बीमा और मातृ-शिशु सुरक्षा योजनाएँ शामिल हैं। नकद हस्तांतरण कार्यक्रम गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करते हैं और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं। वृद्धावस्था पेंशन और अपंग व्यक्तियों के लिए सहायता उन्हें सामाजिक रूप से सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करती हैं। स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ निर्धन वर्ग को गंभीर बीमारियों और चिकित्सकीय खर्चों से राहत देती हैं। मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाकर भविष्य की पीढ़ियों की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।

भारत और अन्य विकासशील देशों में विश्व बैंक के सहयोग से लागू इन कार्यक्रमों ने गरीबी दर में कमी, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समावेशिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी और लाभार्थियों तक पहुँचने में बाधाएँ प्रमुख चुनौतियाँ हैं।¹²

इस प्रकार विश्व बैंक के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निर्धन वर्ग के लिए जीवन की गुणवत्ता सुधारने, जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने और सामाजिक न्याय स्थापित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यदि इन कार्यक्रमों को स्थानीय प्रशासन के सहयोग, पारदर्शिता और जनसहभागिता के माध्यम से और प्रभावी बनाया जाए, तो यह गरीबी उन्मूलन और सतत विकास की दिशा में एक ठोस कदम साबित हो सकते हैं।

प्रभाव

विश्व बैंक की कल्याणकारी योजनाओं ने निर्धन वर्ग के सामाजिक-आर्थिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इन योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार देखने को मिला है। शिक्षा क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा समर्थित परियोजनाओं ने गरीब बच्चों की विद्यालय पहुँच को बढ़ाया तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई और कुपोषण की स्थिति कुछ हद तक सुधरी।¹³

रोजगार और कौशल विकास योजनाओं ने निर्धन वर्ग को आजीविका के नए अवसर प्रदान किए, जिससे उनकी आय और आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। वहीं, आवास और बुनियादी ढाँचे से संबंधित योजनाओं ने स्वच्छ जल, शौचालय और बिजली जैसी सुविधाएँ गरीब समुदायों तक पहुँचाने में योगदान दिया। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों ने निर्धन परिवारों को आर्थिक जोखिमों से आंशिक सुरक्षा प्रदान की।¹⁴

हालाँकि, इन योजनाओं का लाभ अभी भी सभी तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। भ्रष्टाचार, कमजोर क्रियान्वयन और ग्रामीण इलाकों में संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इसके बावजूद, इन योजनाओं ने गरीबी दर में कमी, सामाजिक न्याय और मानव विकास सूचकांकों में सुधार लाने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव डाला है।

चुनौतियाँ

विश्व बैंक द्वारा निर्धन वर्ग की उन्नति और गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच उपलब्ध कराना है। किंतु इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ सामने आती हैं।¹⁵

सबसे पहली चुनौती लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुँच है। अनेक बार योजनाओं का वास्तविक लाभ निर्धन वर्ग तक नहीं पहुँच पाता, बल्कि बीच की नौकरशाही और स्थानीय सत्ता तंत्र में ही अटक जाता है। इससे निर्धन वर्ग योजनाओं से वंचित रह जाता है।¹⁶

दूसरी चुनौती भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी है। योजनाओं के लिए आवंटित धन का एक बड़ा हिस्सा हेरफेर या दुरुपयोग का शिकार हो जाता है। स्थानीय स्तर पर निगरानी की कमी से संसाधन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाते।¹⁷

तीसरी चुनौती सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और विशेषकर महिलाओं तथा वंचित जातियों तक योजनाओं की जानकारी और पहुँच सीमित रहती है। अशिक्षा और जागरूकता की कमी भी इन योजनाओं की प्रभावशीलता को घटाती है।¹⁸

चौथी चुनौती तकनीकी और संरचनात्मक कमी है। अनेक योजनाएँ आधुनिक तकनीक या डिजिटलीकरण पर आधारित होती हैं, जबकि निर्धन वर्ग के पास इंटरनेट, स्मार्टफोन या बैंकिंग सुविधाएँ ही उपलब्ध नहीं होतीं।¹⁹

पाँचवीं बड़ी चुनौती है स्थायित्व की कमी। विश्व बैंक की कई परियोजनाएँ समयबद्ध होती हैं, जिनके समाप्त होने पर लाभार्थियों को पुनः अपनी पुरानी स्थिति में लौटना पड़ता है।²⁰

इन सभी चुनौतियों के कारण विश्व बैंक की कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक और दीर्घकालीन असर अपेक्षित रूप से सामने नहीं आ पाता। जब तक पारदर्शिता, स्थानीय सहभागिता, जन-जागरूकता और बुनियादी ढाँचे को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक निर्धन वर्ग की वास्तविक स्थिति में स्थायी सुधार संभव नहीं है।

निष्कर्ष

विश्व बैंक द्वारा निर्धन वर्ग के लिए चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाएँ गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल आर्थिक रूप से वंचित लोगों की जीवन स्थिति सुधारना है, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में सशक्त बनाना भी है। पोषण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब वर्ग को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुँच प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और वित्तीय सहायता के माध्यम से आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है।

विश्व बैंक की ये योजनाएँ ग्रामीण और शहरी वंचित वर्ग दोनों पर केन्द्रित हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ, आवास और शिक्षा सुविधाओं का विस्तार गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक रहा है। इसके अलावा, महिला सशक्तिकरण और

युवाओं के कौशल विकास के कार्यक्रम समाज में समावेशिता और रोजगार सृजन के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं।

हालांकि, योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। इनमें भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी, लाभार्थियों तक संसाधनों का असमान वितरण और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ प्रमुख हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, विश्व बैंक की योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इससे निर्धन वर्ग के जीवन स्तर में सुधार, गरीबी दर में कमी और सामाजिक समानता की दिशा में प्रगति हुई है।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि विश्व बैंक की कल्याणकारी योजनाएँ निर्धन वर्ग के उत्थान और समाज में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यदि योजनाओं का क्रियान्वयन स्थानीय प्रशासन और समुदाय की भागीदारी के साथ किया जाए, तो ये कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास के लिए प्रभावी और स्थायी साधन बन सकते हैं।

सन्दर्भ-सूची

1. Cammack P. Neoliberalism, the World Bank, and the new politics of development. In: Kothari U, Minogue M, editors. *Development Theory and Practice: Critical Perspectives*. London: Palgrave; 2002. p.157-78.
2. Cammack P. The mother of all governments: the World Bank's matrix for global governance. In: Wilkinson R, Hughes S, editors. *Global Governance: Critical Perspectives*. London: Routledge; 2002. p.36-53.
3. Cammack P. The governance of global capitalism: a new materialist perspective. *Historical Materialism*. 2003;11(2):1-28.
4. Castro-Monge L. Nicaragua and the HIPC initiative: the tortuous journey to debt relief. *Canadian Journal of Development Studies*. 2001;22(2):417-53.
5. Craig D, Porter D. Poverty reduction strategy papers: a new convergence. *World Development*. 2003;31(1):53-69.
6. Dagdeviren H, van der Hoeven R, Weeks J. Poverty reduction with growth and redistribution. *Development and Change*. 2002;33(3):383-413.
7. IMF/World Bank Development Committee. Heavily indebted poor countries (HIPC) initiative: strengthening the link between debt relief and poverty reduction. Washington (DC): World Bank; 1999 Sep 17. Report No.: DC 99-24.
8. Easterly W. How did heavily indebted poor countries become heavily indebted? Reviewing two decades of debt relief. *World Development*. 2002;30(10):1677-96.
9. Fine B. Neither the Washington nor the post-Washington consensus: an introduction. In: Fine B, Lavitsas C, Pincus J, editors. *Development Policy in the Twenty-First Century: Beyond the Washington Consensus*. London: Routledge; 2001. p.1-27.
10. Fine B. The World Bank's speculation on social capital. In: Pincus J, Winters J, editors. *Reinventing the World Bank*. Ithaca (NY): Cornell University Press; 2002. p.203-21.
11. Fox J, Gershman J. The World Bank and social capital: lessons from ten rural development projects in the Philippines and Mexico. *Policy Sciences*. 2000;33(3-4):399-419.
12. Francis P, James R. Balancing rural poverty reduction and citizen participation: the contradictions of Uganda's decentralization program. *World Development*. 2003;31(2):325-37.
13. Gilbert C, Powell A, Vines D. Positioning the World Bank. In: Gilbert C, Vines D, editors. *The World Bank: Structure and Policies*. Cambridge: Cambridge University Press; 2000. p.39-86.
14. Gilbert C, Vines D, editors. *The World Bank: Structure and Policies*. Cambridge: Cambridge University Press; 2000.
15. Gilbert C, Vines D. The World Bank: an overview of some major issues. In: Gilbert C, Vines D, editors. *The World Bank: Structure and Policies*. Cambridge: Cambridge University Press; 2000. p.10-36.
16. Government of Nicaragua. *A Strengthened Poverty Reduction Strategy*. Managua: Government of Nicaragua; 2000 Aug.
17. Government of Nicaragua. *Strengthened Growth and Poverty Reduction Strategy (SGPRS) First Progress Report*. Managua: Government of Nicaragua; 2002 Nov.
18. Hans VB. Towards a vibrant Indian agriculture. *Kisan World*. 2006;Feb:1-3.
19. World Bank. New country classifications 2016 [Internet]. Washington (DC): World Bank; [cited 2025 Oct 11]. Available from: <http://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-2016>
20. Indian Institute of Banking and Finance (IIBF). Financial inclusion [Internet]. Mumbai: IIBF; [cited 2025 Oct 11]. Available from: http://iibf.org.in/iib_financeinclusion.asp